



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 16 मई, 2007/26 वैशाख, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 16 मई, 2007

संख्या एल० एल० आर०-डी०(६)४/२००७-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11-05-2007 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) विधेयक, 2007 (2007 का

विधेयक संख्यांक 5) को वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
↓

हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2007

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 11 मई, 2007 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संक्षिप्त नाम। (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2007 है ।

2005 का 12

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके धारा 11 का पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 में,— संशोधन ।

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), जिसके लिए क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् 'क्रेता व्यौहारी' कहा गया है), कर अवधि के दौरान उसके द्वारा कराधेय विक्रयों की बाबत दावा कर सकेगा—

- (i) ऐसे क्रेता व्यौहारी द्वारा विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को, ऐसे माल के क्रय के आवर्त पर, जिसका उसके द्वारा कर अवधि के दौरान विक्रय किया गया है, संदत्त या संदेय आगत कर की रकम होगी; और
- (ii) इस धारा में यथा उपबंधित के अनुसार संगणित और अनुज्ञात किया जाएगा तथा ऐसी अन्य शर्तों के अध्यक्षीन होगा जैसी विहित की जाएं ।"

(ख) उप-धारा (3) में—

“आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) क्रेता व्यौहारी द्वारा राज्य में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जो विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रखता हो, क्रय किए गए कराधेय माल पर संदत्त आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम की सीमा तक ही अनुज्ञात किया जाएगा, जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आशयित हों,—” शब्दों, चिन्हों तथा कोष्ठकों के स्थान पर “आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), सिवाय उस माल के, जिसके विषय में इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) अनुज्ञेय नहीं है, क्रेता व्यौहारी को, ऐसे कराधेय माल, जिसे उसके द्वारा कर अवधि के दौरान विक्रय किया गया है, के विक्रयों के आवर्त की बाबत और रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जो विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रखता हो, क्रय किए गए कराधेय माल पर संदत्त आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम की सीमा तक ही निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,—” शब्द, चिन्ह और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) उप-धारा (7) के खण्ड (ट) के उप-खण्ड (iii) के पश्चात् “।” चिन्ह के स्थान पर, “ ; और ” चिन्ह तथा शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात् नया खण्ड (ठ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ठ) ऐसे माल के क्रय का आवर्त जिसे कर अवधि के दौरान विक्रीत नहीं किया गया है ।” ;

(घ) उप-धारा (9) में “आशयित है” शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(ङ) उप-धारा (13) में स्पष्टीकरण में, भाग (i) में “जिसके लिए क्रेता व्यौहारी हकदार है” शब्दों के स्थान पर “जिसके लिए क्रेता व्यौहारी को कर अवधि के दौरान उसके द्वारा कराधेय विक्रयों की बाबत इस धारा के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा, ” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 62 का
संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 62 में उप-धारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(7) उप-धारा (5) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्य सरकार, भूतलक्षी प्रभाव से, कर का आस्थगित संदाय करने की सुविधा का उपबन्ध करने हेतु

अधिसूचना जारी कर सकेगी या स्कीम बना सकेगी ताकि अप्रैल, 2005 के प्रथम दिन या के पश्चात् किसी भी दिन प्रभावी हो सके ।”।

4. (1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) विधिमाम्य-अधिनियम, 2007 (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है) द्वारा करण । यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (5) के उपबंध इस तथ्य के होते हुए भी कि यह तत्पश्चात् अधिनियमित किया गया है, अप्रैल, 2005 के प्रथम दिवस से विधिमाम्य और प्रभावी समझे जाएंगे और सदैव प्रभावी समझे जाते रहेंगे, और तदनुसार—

(क) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), तारीख 31 मार्च, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ(1)-2/2004(iii), तारीख 30 मार्च, 2005 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (डैफरड पेमेंट ऑफ टैक्स) स्कीम, 2005 (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “उक्त स्कीम” कहा गया है) के पैरा 5-ए में विनिर्दिष्ट नई तथा विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को, निम्नलिखित के लिए, विकल्प (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “उक्त विकल्प” कहा गया है) अनुज्ञात किया गया समझा और सदैव अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा—

- (i) या तो उक्त स्कीम में यथा उपबंधित कर का आस्थगित संदाय करने की सुविधा का उपभोग करना जारी रखे ; या
- (ii) उक्त स्कीम से संलग्न प्ररूप एस0 टी0 (डी0 पी0)—VII के निबन्धनों के अनुसार आवेदन करके आस्थगित कर दायित्व का, पैसठ प्रतिशत के शुद्ध वर्तमान मूल्य पर आस्थगित कर की रकम का संदाय तुरन्त (अपफ्रन्ट) करे ; और

(ख) उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 62 के अनुसरण में जारी की गई किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट पैसठ प्रतिशत के शुद्ध वर्तमान मूल्य पर आस्थगित कर की रकम का तुरन्त (अपफ्रन्ट) संदाय करने का उक्त विकल्प, केवल आस्थगित कर की रकम तक निर्बन्धित समझा जाएगा और सदैव निर्बन्धित समझा जाता रहेगा;

और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय या डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित

मूल अधिनियम की धारा 62 के अनुसरण में जारी कोई भी अधिसूचना या स्कीम,—

- (I) या तो उक्त स्कीम में यथा उपबन्धित कर का आस्थगित संदाय करने की सुविधा का उपभोग जारी रखने, या
- (II) उक्त स्कीम से संलग्न प्ररूप एस0 टी0 (डी0 पी0)—VII के निबन्धनों के अनुसार आवेदन करके आस्थगित कर दायित्व का ऍसट प्रतिशत के शुद्ध वर्तमान मूल्य पर तुरंत (अपफ्रन्ट) आस्थगित कर की रकम का संदाय करने के लिए ;

केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी या सदैव अविधिमान्य नहीं समझी जाती रहेगी कि ऐसी अधिसूचना या ऐसी स्कीम जारी करने वाले प्राधिकारी को उनको जारी करने का प्राधिकार नहीं था, और तदनुसार—

- (i) किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण अथवा प्राधिकरण के समक्ष किसी कर ब्याज या शास्ति के प्रतिदाय के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, और किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी कर, ब्याज या शास्ति जिसे संगृहीत किया गया है, के प्रतिदाय का निदेश देने वाली किसी डिक्री या आदेश का प्रवर्तन नहीं किया जाएगा ;
- (ii) उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार उन सभी रकमों की वसूलियां, यदि कोई हो, की जाएंगी, जो तदधीन संगृहीत की गई होती, मानों उक्त अधिनियम सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ; और
- (iii) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (किसी नियम या किए गए आदेश, जारी की गई अधिसूचना या स्कीम, दिया गया निदेश या अधिरोपित अथवा वसूल किए गए कर, ब्याज या शास्ति सहित), जो जहां तक कि जो उक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो , उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सदैव विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को निम्नलिखित करने से निवारित करती है—

- (i) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर के निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण को उक्त विकल्प के अनुसार प्रश्नगत करने ; या
- (ii) उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन उससे देय रकम से अधिक, उसके द्वारा संदत्त कर, ब्याज या शास्ति के प्रतिदाय का दावा करने ; और
- (iii) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य या लोप, दंडनीय अपराध नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता मानो उक्त अधिनियम प्रवृत्त ही नहीं हुआ था ।

Act No. 12 of 2007

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX
(AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2007**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 11TH MAY, 2007)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005
(Act No. 12 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh
in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added
Tax (Amendment and Validation) Act, 2007.

Amendment
of section
11.

2. In section 11 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act,
2005 (hereinafter referred to as the “principal Act”),—

12.

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted,
namely:—

“(1) Subject to the provisions of this Act, the input
tax credit which a purchasing registered dealer
(hereinafter in this section called ‘the purchasing
dealer’) may claim, in respect of taxable sales made
by him during the tax period, shall be—

- (i) the amount of input tax paid or payable by such
purchasing dealer to the selling registered dealer,
on the turnover of purchases of such goods as
have been sold by him during the tax period;
and
- (ii) calculated and allowed as provided in this
section, and subject to such other conditions as
may be prescribed.”;

- (b) in sub-section (3), for the words and the signs "The input tax credit shall be allowed to the extent of the amount of input tax paid by the purchasing dealer on the purchases of taxable goods made by him in the State, from a registered dealer holding a valid certificate of registration, which are intended for the purposes of,-", the words and signs "Except the goods in respect of which input tax credit is not admissible under this Act or the rules made thereunder, the input tax credit shall be allowed to the purchasing dealer in respect of the turnover of purchases of such taxable goods as have been sold by him during the tax period, and to the extent of the amount of input tax paid by such purchasing dealer on the turnover of purchases of such taxable goods made by him in the State, from a registered dealer holding a valid certificate of registration, for the purposes of,-" shall be substituted;
- (c) in sub-section (7), in clause (k), in sub-clause (iii), for the sign ".", the sign and the word "; and" shall be substituted and thereafter the following new clause shall be inserted, namely:—
- “(l) the turnover of purchase of such goods which have not been sold during the tax period.”;
- (d) in sub-section (9), the words “are intended” shall be omitted; and
- (e) in sub-section (13), in the Explanation, in part (i), for the words “for which the purchasing dealer is entitled to”, the words “which the purchasing dealer may be allowed under this section in respect of taxable sales made by him during the tax period” shall be substituted.

3. In section 62 of the principal Act, after sub-section (6), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment
of section 62.

- “(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (5), the State Government may, issue a

notification or make a Scheme, to provide for facility of making deferred payment of tax, with retrospective effect so as to be effective from any day on or after 1st day of April, 2005. ”.

Validation.

4. (1) The provisions of sub-section (5) of section 62 of the principal Act, as amended by the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment and Validation) Act, 2007(hereinafter in this section referred to as the 'said Act'), shall be deemed to be and to have always been valid and effective from the 1st day of April, 2005 irrespective of the fact that it has been enacted subsequently, and accordingly—

(a) the new and existing industrial units specified in para 5-A of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Deferred Payment of Tax) Scheme, 2005, (hereinafter in this section referred to as the “said Scheme”) notified *vide* Notification No. EXN-F(1)-2/2004-(iii) dated 30th March, 2005 published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 31st March, 2005, and as amended from time to time, shall be deemed to be and shall be deemed always to have allowed the option(hereinafter in this section referred to as the 'said option')—

(i) either to continue to avail of the facility of making deferred payment of tax as provided for in the said Scheme; or

(ii) by making an application, in terms of Form S.T. (DP)-VII appended to the said Scheme, to pay the amount of deferred tax upfront at the net present value of 65% of the deferred tax liability; and

(b) the said option to pay the amount, of the deferred tax upfront at the net present value of 65% specified in any notification issued in pursuance of section 62 of the principal Act, as amended by the said Act, shall be deemed to be and shall be deemed always to have been restricted to the amount of the deferred tax liability only;

and notwithstanding any judgment or decree or order of any court, Tribunal or authority to the contrary, no notification or Scheme which has been issued in pursuance of section 62 of the principal Act, as amended by the said Act,—

- (I) either to continue to avail of the facility of making deferred payment of tax as provided for in the said Scheme, or
- (II) by making an application in terms of Form S.T. (DP)-VII, appended to the said Scheme, to pay the amount of deferred tax upfront at the net present value of 65% of the deferred tax liability;

shall be deemed to be invalid or ever to have been invalid on the ground merely that the authority issuing such notification or such Scheme did not have competence to issue the same, and accordingly—

- (i) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any court or before any Tribunal or authority for the refund of any tax, interest or penalty, and no enforcement shall be made by any court, Tribunal or authority of any decree or order directing the refund of the tax, interest or penalty which has been collected;
- (ii) recoveries, if any, shall be made, in accordance with the provisions of the principal Act, as amended by the said Act, of all amounts which would have been collected thereunder, as if the said Act had been in force at all material times; and
- (iii) anything done or any action taken (including any rule or order made, notification or Scheme issued or direction given or tax, interest or penalty imposed or recovered) under the principal Act before the commencement of the said Act, in so

far as it is not inconsistent with the provisions of the said Act, shall be deemed always to have been validly done or taken in accordance with provisions of the principal Act as amended by the said Act.

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in sub-section (1) shall be construed as preventing any person—

- (i) from questioning, in accordance with the provisions of the said Act, the assessment, levy or collection of the tax as per the said option; or
- (ii) from claiming refund of the tax, interest or penalty paid by him in excess of the amount due from him under the principal Act as amended by the said Act; and
- (iii) no act or omission on the part of any person, before the commencement of the said Act, shall be punishable as an offence which would not have been so punishable as if the said Act had not come into force.